मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

- खट्टर को सता रही है ईएसआई मेडिकल कॉलेज की याद 3
- लाला रामदेव का धंधा न कभी पड़ा मंदा 4
- मोदी के 15 लाख के झूठे वादे पर नाना के असली 15 हजार भारी
- यूपी में चुनाव : गुंडाराज, महागुंडाराज या राक्षसराज 5
- अपराधियों को भी चाहियें लूट के लोकतांत्रिक अधिकार 8
- सीपी विचलित, क्या करें, क्या न करें

वर्ष 29 अंक 16 फरीदाबाद, शुक्रवार 1-15 जुलाई 2016 फोन : - 9999595632 2 ₹

बस्सी व शरद कुमार को मिला कानून से गद्दारी का पुरस्कार

राजनीतिक मिसाइल बना मोदी का फ़ासीवादी विधिशास्त्र

'आप' पार्टी के हर विधायक के सिर पर गिरफ़्तारी की तलवार लटक रही है। इस दिशा में दिल्ली पुलिस के पास जाबता खंगालने की पूरी छूट है। इसके ठीक उलट भाजपा के किसी विधायक, आरएसएस प्रचारक या सांसद को गिरफ़्तार न करने का अलिखित कानून भी देश मे लागू है। यही सुविधा बड़े कार्पोरेट समुदाय को भी मिली हुई है। इन लोगों को साम्प्रदायिक उन्माद फ़ैलाने से लेकर जनता का सैंकड़ों-हज़ारों करोड़ रुपया हजम करने की छुट्टा छोड़ा हुआ है। लगता है देश में एक नये विधिशास्त्र की रचना हो रही है। पुलिस वालों की नज़रों से कहीं यह रह न जाय, इसलिये इस विधिशास्त्र पर चलने वाले दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर भीमसेन बस्सी को सेवा निवृत होने पर संघ लोक सेवा आयोग की सदस्यता से नवाजा गया है। इसी तरह एनआईए प्रमुख शरद कुमार के सेवाकाल में भी लगातार वृद्धि की जा रही है। विडम्बना यह है कि पुलिस की मार्फ़त लिखा जा रहा विधिशास्त्र, न्यायपालिका के लिये भी शिरोधार्य सिद्ध हो रहा है।

मज़दूर मोर्चा, दिल्ली ब्यूरो

संगम बिहार में 'आप' सरकार द्वारा पानी की समस्या हल होती देख बरसों से पनप रहे सशक्त जल-माफ़िया का परेशान होना स्वाभाविक था। लिहाज़ा जनता को राहत दिलाने वाली 'आप' सरकार के विधायक दिनेश मोहनिया, जो दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं को जेल भिजवाने के लिये मोदी सरकार से हाथ मिला लिया। नकली ड्रामा करके पहले भाड़े की कुछ महिलाओं से विधायक के विरुद्ध झूठी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गयी। मूल शिकायत के अनुसार गंभीर धारायें नहीं बन पा रही थी तो दिल्ली पुलिस के ही मार्ग दर्शन में शिकायत को संशोधित करके यौनिक दुर्व्यवहार जोड़ दिया गया। इसके आधार पर मोहनिया को प्रेस कांफ्रेंस से उठा कर पुलिस ले गयी। दिल्ली पुलिस के हाथों गिरफ़्तार होने वाले माहनिया 'आप' पार्टी के 8 वें विधायक हैं। भारत की किसी भी विधान सभा में यह एक रिकार्ड सरीखा है।

पूर्व में गिरफ़्तार 'आप' के विधायकों पर लोकसेवकों से दुर्व्यवहार, फ़र्जी शैक्षणिक डिग्री, पत्नी उत्पीड़न (जिसमें एक कुत्ते को गवाह रखा गया), अनुसूचित जाति अधिनियम जैसे 'तकनीकी' आरोप हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को उस टैंकर घोटाले में लपेटा जा रहा है जो कांग्रेसी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के जमाने में हुआ था। विडम्बना यह कि इस मामले की जांच करा कर एफ़आईआर दर्ज करने की हलचल स्वयं केजरीवाल ने ही शुरू की थी।

दिल्ली पुलिस यदि उपरोक्त कानूनी मानदंडों को औरों पर भी लागू करे तो उसे अब तक अम्बानी बंधुओं, शीला दीक्षित, कांग्रेसी पूर्व मंत्री वीरप्पा मोइली, दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग, मोदी की शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी और तमाम साम्प्रदायिक विष वमन करते हिन्दुत्ववादियों को कब की हवालात की हवा खिला देनी चाहिये थी। इन सबके विरुद्ध कबके गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हो जाने चाहिये थे।

दिल्ली पुलिस की भूमिका को लेकर बेहद चुभने वाला मामला जेएनयू का रहा है। बिना तफ़्तीश शुरू किये ही अंधा धुंध छात्रों की गंभीर धाराओं में गिरफ़्तारी की गयी। यहां तक कि घृणा फ़ैलाने के लिये सुभाष चन्द्रा के जी टीवी समेत कई मीडिया चैनलों ने जेएनयू के फ़र्जी टेप बनाकर चलाये। इस मामले में किसी की गिरफ़्तारी तो दूर, सुभाष चन्द्रा को भाजपा ने पुरस्कार-स्वरूप हरियाणा से राज्य सभा सदस्य बना दिया। यानी विधिशास्त्र किस की मर्जी से सिर के बल खड़ा किया जा रहा है, इसमें रंच मात्र भी शक की गुंजायश नहीं रह गयी है।

इसी संदर्भ में दिल्ली पुलिस व मोदी सरकार का वह करिश्मा भी गौरतलब है, जिसमें पुलिस हिरासत में कोर्ट में पेश होते वक्त जेएनयू छात्र कन्हैया व कुछ पत्रकारों सहित कई संभ्रांत व्यक्तियों को संघ के गुंडों ने पीटा था, और कहीं नहीं कोर्ट कक्ष में मैजिस्ट्रेट के सामने व कक्ष के बाहर। सारी वारदात बाकायदा कैमरों में कैद हुई। चंद कदम दूर बैठी हाई कोर्ट व

शेष पेज दो पर

इमरजेंसी बनाम अघोषित इमरजेंसी

तेरा कया होगा शरद कुमार ?

मुंबई स्थित विशेष एनआईए कोर्ट ने मालेगांव धमाकों की अभियुक्त साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जमानत देने से साफ़ इन्कार कर दिया। जबकि मोदी सरकार एवं संघ के हाथों बिके एनआईए व उसके वकील ने जमानत का विरोध करने की बजाय, जमानत दिलाने के लिये पूरा ज़ोर लगाया था। जज ने एनआईए को लताड़ते हुए कहा कि इस से पहले की गयी मुंबई पुलिस की तफ़्तीश में प्रज्ञा के विरुद्ध अकाट्य सबूत मौजूद हैं।

तमाम हिन्दुत्ववादियों को आरोप मुक्त कराने का ठेका लेकर सेवा विस्तार पर चल रहे शरद कुमार का अब क्या होगा? पुरस्कार-स्वरूप कोई नया पद मिलेगा भी या नहीं?

ख़बर दार

गोलियां न गिनने वाला गृहमंत्री

जब भी पाकिस्तान सीमा पर कोई हादसा होता है या आतंकियों द्वारा सुरक्षाबलों को नुक्सान पहुंचाया जाता है तो केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिये बिल से बाहर निकल आते हैं। और तो कुछ खास होता नहीं उनके पास कहने को, हां एक रटा-रटाया जुमला जरूर बोल कर वे भाड़े की भीड़ से तालियां जरूर बजवा लेते हैं। ''...पहली गोली हमारी तरफ़ से नहीं चलेगी, लेकिन उनकी तरफ़ से एक गोली चलने के बाद फ़िर हमें गोलियां गिनने की जरूरत नहीं...'' जबकि सैन्य बलों का नियम है कि हर चली गोली का हिसाब-किताब रखना पड़ता है। 'मज़दूर मोर्चा' ने राजनाथ सिंह से काल्पनिक साक्षात्कार में अन्य बातों के अलावा इसका भी खुलासा लिया।

म.मो.-गृहमंत्री जी पहले तो यह बताइये कि पाकिस्तान की ओर से आनेवाली गोलियों को इतने मजबूत और मुखर प्रधानमंत्री के होते हुए भी आप लोग क्यों नहीं रोक पा रहे?

राजनाथ-यही तो हमारे भी समझ में नहीं आ रहा। मोदी जी इतनी अच्छी गर्जना करते हैं, यहां तक कि हमने पहले बाप और फ़िर बेटी से मिल कर काशमीर में सरकार भी बना ली, और तो और मोदीजी नवाज शरीफ़ के घर शादी की दावत भी उड़ा आये, तो भी उनकी ओर से गोलियां आनी बंद नहीं हो रही। अब तो बस यही रह गया है कि पाकिस्तानी सेना के जनरलों और वहां के मुल्लाओं को घूस-घास देकर मामला निपटाया जाय। लेकिन ये बातें मैं सार्वजनिक रूप से व्यक्त नहीं कर सकता।

म.मो.-राजनाथ जी आपने जो परिस्थिति बयान की है हमारी पूरी सहानुभूति आपके साथ है। ज़रा यह तो बताइये कि आप भारतीय सैनिकों को बिना गिने गोलियां चलाने की सलाह क्यों देते हैं? क्या इससे दुश्मन का ज़्यादा नुक्सान होगा?

राजनाथ-यही तो राना है कि जितनी मर्जी उतनी गोलियां चला लो, दुश्मन का कोई नुक्सान नहीं होता। वह भी तो बंकरों में छुपा रहता है जहां गोलियां असर नहीं डालती। जब मोदी जी इतनी जुमलेबाजी करते हैं तो उनके गृहमंत्री को भी तो जुमलेबाज़ी करनी ही चाहिये।

म.मो.-लेकिन बिना गिने क्यों? आपकी शिक्षा मन्त्री बेशक पढी-लिखी न हो लेकिन सैनिक तो पढ़ा-लिखा होता है। वैसे भी उसे गिन कर गोलियां दी जाती हैं और गिन कर खाली खोल वापस लिये जाते हैं।

राजनाथ-अरे भाई इस तरह हम यह दावा करने योग्य तो हो जाते हैं कि हमने उनके मुकाबले कहीं अधिक गोलियां चलाई हैं। बाकी तो आप देख ही रहे हो- न हमसे दाऊद इब्राहीम पकड़ा गया, न हम अपने काशमीर में 'पाकिस्तान जिन्दाबाद' रोक पाये, और आतंकी घटनायें भी बढ़ती ही चली जा रही हैं।

म.मो.-इस विषय में आपकी भावी योजनायें क्या हैं?

राजनाथ-यह तो हम अमेरिका से पूछ कर ही बता पायेंगे। हमें पूरी आशा है कि मोदी जी और ओबामा जी की दोस्ती के चलते एक न एक दिन काशमीर में शान्ति जरूर आयेगी।

म.मो.-आप लोग कांग्रेसी सरकार से किस तरह भिन्न हुए?

राजनाथ-अब आपने अक्ल की बात पूछी कांग्रेसी गृहमंत्री गिन कर गोलियां चलवाते थे जबकि हम बिना गिने चलवाने पर जोर देते हैं। क्या यह अन्तर कुछ कम है?

चीनी एनएसजी बनाम स्वदेशी एनएसजी

चीन ने बार-बार स्पष्ट कर दिया था कि उसकी सदस्यता वाले एनएसजी (न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप) में वह भारत को प्रवेश नहीं करने देगा। अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति में देशों के अपने हित सर्वोपरि होते हैं जो मात्र वाक्चातुर्य से नहीं बदला करते। इस मूल बात को न समझ पाने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने सारी दुनिया में अपनी और अपने दूतों की उछल-कूद मचा कर भारत की अच्छी-खासी भद्द पिटवाई। वे सोचते होंगे कि उनका 56 इन्च का सीना और 10 लाख का सूट जो विदेशों में भाड़े के टट्टुओं से 'मोदी-मोदी' का अर्तनाद कराते हैं, उन्हें एनएसजी की सदस्यता भी दिला पायेंगे। यह न होना था न हुआ।

मोदीगान करने वाले तब भी पीछे हटने को तैयार नहीं। उनके हिसाब से चीन से आये सामानों का बहिष्कार करके देशवासियों को उसे मुंहतोड़ जवाब देना चाहिये। वे लगातार एक-दूसरे से बढ-चढ कर बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने सस्ते चीनी सामानों के बजाय महंगे भारतीय सामानों को खरीद कर राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया है। मोदीभक्तों को ज़रा भी समझ होती तो वे सीधा सवाल खड़ा करते कि चीन निर्मित सामानों को भारत में आने ही क्यों दिया जा रहा है? मोदी सरकार एक दिन में इस पर रोक लगा सकती है। इससे न केवल चीन को सबक मिलेगा बल्कि भारतीय उद्योग भी फलेंगे-फूलेंगे जिससे स्थानीय कामगारों को अधिक रोजगार भी मिलेगा। विडम्बना यह कि इन भक्तों के घरों में तमाम उपभोक्ता चीनी सामान भरा पड़ा है, जिसका बहिष्कार वे नहीं करना चाहते।

दरअसल मोदी भक्तों को चीनी एनएसजी भूल कर अपनी स्वदेशी एनएसजी (ना समझ ग्रुप) को मजबूत करना चाहिये। इसमें चीन सहित समझदार भारतीयों को भी प्रवेश की इजाजत नहीं होनी चाहिये। दरअसल, ना समझ ग्रुप की सक्रियता 2014 में नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बेतरह बढ गयी है। उल्लेखनीय है कि इसी अनुपात में आम जनता का मोदी सरकार से मोहभंग भी बढ़ता जा रहा है।